

राजस्थान-सरकार
कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
जयपुर ग्रामीण

☎ :- 0141-2209776

E Mail-sjejaipururural@yahoo.co.in

क्रमांक : एफ 1/स्था./सान्याआवे/2018/11700


दिनांक 24.04.2018

निविदा सूचना

ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय में पंचायत समिति स्तर पर 10 स्थानों पर (गोविन्दगढ, कोटपूतली, जमवारामगढ, फागी, पावटा, विराटनगर, दूदू, चाकसू, बस्सी, शाहपुरा) डाटा कम्प्यूटराईजेशन कार्य हेतु वर्ष 2018-19 में 10 मशीन विद् मैन 28 फरवरी 2019 अथवा उक्त पदों पर नियमित कर्मचारी पदस्थापित होने तक जो भी पहले हो तक संविदा/अनुबंध पर लिया जाना है। जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत/प्राधिकृत एवं अनुभवी सेवा एजेन्सी से निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

क्र. स.	अनुमानित लागत (लाखों में)	निविदा पत्र शुल्क	अमानत राशि (अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत)	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय
1	8.50	500.00	17000	09.05.2018 दोपहर 2.00 बजे	09.05.2018 साय: 3.00 बजे

1. निविदा की विस्तृत सूचना एवं शर्तें कार्यालय के नोटिस बोर्ड, विभागीय वेबसाईट www.sje.rajasthan.gov.in एवं sppp portal पर उपलब्ध है।


उपनिदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जयपुर (ग्रामीण)



राजस्थान-सरकार
कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
जयपुर ग्रामीण

☎:- 0141-2209776

E Mail-sjejaipurrural@yahoo.co.in

निविदा पत्र

ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालयों हेतु वर्ष 2018-19 में मशीन विद् मैन जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत/प्राधिकृत एवं अनुभवी सेवा प्रदाता से निविदाये आमंत्रित की जाती है:-

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली संस्था/फर्म/एजेन्सी का नाम तथा डाक का पूरा पता

.....
.....

दूरभाष:-मोबाइल:-

2. संदर्भ निविदा विज्ञप्ति क्रमांक दिनांक

3. निविदा शुल्क की नगद जमा राशि रु. रसीद संख्या दिनांक

4. धरोहर राशि हेतु उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर ग्रामीण के पक्ष में जारी बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट सं. दिनांक राशि रु.

संलग्न है।

5. मशीन विद् मैन संबंधी सेवा प्रदाय करने हेतु जी.एस.टी. पंजीयन सं.

दिनांक वैधता अवधि

(प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।)

5. आयकर विभाग

6. द्वारा जारी परमानेंट अकाउन्ट नम्बर (पैन).....

7. कार्यानुभव का विवरण :-

(प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न करें।)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	अवधि
1.		
2.		
3.		
4.		

- 8 उपर्युक्त अंकित दरें दिनांक 28.02.2019 तक वैध है। समयावधि में वृद्धि पारस्परिक सहमति से की जा सकती है।
- 9 जी.एफ.एण्ड ए.आर. एवं आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 एवं 2013 के प्रावधान एवं वित्त विभाग के दिशा निर्देश प्रभावी रहेंगे।
- 10 निविदा सूचना संख्या दिनांक जो कि उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर ग्रामीण के द्वारा जारी की गई है, में वर्णित समस्त शर्तों की पालना के लिए हम सहमत हैं तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तें जो संलग्न पृष्ठ में दी गई हैं जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने की प्रतीक स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं का भी पालन करने के लिए हम सहमत हैं।
- 11 मशीन विद् मैन संबंधी कार्य निविदा अमानत राशि 17000.00 रुपये होगी। जो उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण के नाम डी.डी./बैंकर्स चेक से जमा करवाई जावेगी।
- 12 किसी भी माह में चार दिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद नहीं रखा जायेगा। इससे अधिक कम्प्यूटर बंद रहने पर 200/- रुपये की प्रतिदिन से कटौति की जायेगी।

दिनांक:

हस्ताक्षर निविदादाता

कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर ग्रामीण

निविदा की सामान्य शर्त:-

1. ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय में पंचायत समिति स्तर पर 10 स्थानों पर (गोविन्दगढ़, कोटपूतली, जमवारामगढ़, फागी, पावटा, विराटनगर, दूदू, चाकसू, बस्सी, शाहपुरा) डाटा कम्प्यूटराईजेशन कार्य हेतु वर्ष 2018-19 में 10 मशीन विद मैन 28 फरवरी 2019 अथवा उक्त पदों पर नियमित कर्मचारी पदस्थापित होने तक जो भी पहले हो तक निविदा/अनुबंध पर लिया जाना है। जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत/प्राधिकृत एवं अनुभवी सेवा एजेंसी से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।
2. कार्यालय उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर ग्रामीण के अधीनस्थ 10 ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय में मशीन विद मैन की सेवाएं ली जानी हैं।
3. कार्य की अवधि कार्यदेश स्वीकृति की तिथि से दिनांक 28.02.2019 तक मान्य होगी। जिसे उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण द्वारा आपसी सहमति से निविदा अनुबंध अवधि एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती हैं।
4. निविदादाता/संस्था/फर्म/एजेंसी को पूर्व में राजकीय कार्यालयों, अर्द्धशासकीय कार्यालयों में या अन्य संस्थाओं में निविदा में उल्लेखित कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतियाँ निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
5. निविदादाता को निविदा सूचना में अंकित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/नकद द्वारा निविदा के साथ जमा करानी होगी। सफल निविदादाता की धरोहर राशि को प्रतिभूति/जमानत राशि (S.D.) में समायोजित कर लिया जाएगा। द्वितीय न्यूनतम दर निविदादाता की धरोहर राशि रोक कर शेष निविदादाताओं को आवेदन करने पर धरोहर राशि लौटा दी जाएगी। धरोहर राशि के बिना प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण को होगा।
7. निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्र या कोई त्रुटि पाये जाने पर निविदा को रद्द करने का अधिकार उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण को होगा।
8. न्यूनतम दरों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण के पास सुरक्षित होगा।

9. जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
10. मशीन विद् मैन स्वयं को ही सप्लाई करना होगा, वह किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को सबलेट नहीं करेगा।
11. मशीन विद् मैन संबंधी कार्य की शर्तों का उल्लंघन होने पर बिना नोटिस दिये मशीन विद् मैन संबंधी कार्य निरस्त कर दिया जाएगा।
12. मशीन विद् मैन संबंधी कार्य के सम्बन्ध में अन्य कोई शर्तें मान्य नहीं होगी। सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
13. निविदाकर्ता पर सामान्य वित्तीय लेखा नियम एवं आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 एवं 2013 के प्रावधान लागू होंगे।
14. निविदा अनुमोदन होने पर संबन्धित संस्था/फर्म/एजेन्सी द्वारा नियमानुसार शुल्क का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर निर्धारित प्रपत्र में अनुबन्ध प्रस्तुत करना होगा जिसका समस्त व्यय संबन्धित फर्म द्वारा वहन किया जाएगा। सफल निविदादाता को अनुमोदित कार्य राशि की 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में डी. डी./बैंकर चैक/नगद/राष्ट्रीय बचत पत्र (जो कि निविदादाता के नाम से क्रय किये गये हो एवं उपनिदेशक जयपुर ग्रामीण के हक में समर्पण मूल्य में प्लेज करा कर प्रस्तुत किये हों) प्रस्तुत करनी होगी। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
15. निविदाकर्ता द्वारा कार्य बीच में छोड़ने पर या उसका कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में निविदाकर्ता को स्वीकृत मशीन विद् मैन के कार्य को निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त करने का पूर्ण अधिकार उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण को होगा।
16. यदि निविदाकर्ता के किसी कृत्य या अकृत्य से व्यथित होकर कर्मकार न्यायालय में आनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है और इसमें तो उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण प्रशासन को भी पक्षकार बनाता है उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण प्रशासन पर पड़ने वाला समस्त भार निविदाकर्ता से वसूला जाएगा।
17. यदि निविदाकर्ता एवं कर्मकारों के मध्य कोई विवाद होता है तो उसकी जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी। उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण के प्रशासन का कोई दायित्व नहीं होगा।
18. निविदा खोलने की तिथि से तीन माह की अवधि के लिये विधि मान्य होगी।
19. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण का निर्णय अंतिम होगा व निविदाकर्ता को मानना होगा।

20. आयकर, सेवाकर एवं अन्य कटौतियां राज्य सरकार के नियमानुसार की जावेगी।
21. निम्नांकित स्थितियों में धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
- (1) यदि निविदादाता मशीन विद् मैन की निविदा के खुलने के बाद परन्तु उसकी स्वीकृति पूर्व में अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या संशोधित करता है।
- (2) यदि निविदादाता निर्धारित अवधि में अनुबन्ध निस्तारित नहीं करता है।
22. किसी प्रकार का विवाद होने पर कानूनी कार्यवाही जयपुर स्थित न्यायालय में ही होगी।
23. निविदाकर्ता को निर्धारित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर तीन दिवस की अवधि में अनुबंध प्रस्तुत करना होगा, जिसका समस्त व्यय अनुबंधित फर्म द्वारा वहन किया जावेगा।
24. किसी भी मशीन विद् मैन के कार्य बिन्दु पर कार्य न होने या आंशिक कार्य हाने की स्थिति में उस बिन्दु की बनने वाली पूर्ण राशि की कटौती निविदाकर्ता के बिल में से की जावेगी।
25. बिल एवं बिल के साथ समस्त संलग्नकों पर निविदाकर्ता या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति से ही हस्ताक्षर मय नाम एवं मोहर अंकित होना आवश्यक है। बिल पर सेवाप्रदायकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर होने पर बिल पर कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा। विलम्ब के लिये निविदाकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
26. यदि निर्धारित मशीन विद् मैन के कार्य बिन्दुओं पर कार्य व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई तो उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण के निर्देशानुसार किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। सुरक्षा राशि जब्त कर ली जावेगी।
27. किसी भी निविदा अनुबंध को बिना कारण बताये निरस्त/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण को होगा।
28. निविदाकर्ता का जी.एस.टी. में पंजीकृत होना आवश्यक है। पंजीयन प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। निविदाकर्ता को भुगतान कोषालय से पारित बिल राशि में से नियमानुसार स्रोत पर आयकर (टी.डी.एस.) की कटौती कर शेष सम्पूर्ण राशि का ऑन लाईन भुगतान किया जावेगा।
29. निविदाकर्ता द्वारा कार्य बीच में छोड़ने पर अनुबंध की शर्तों की पालना नहीं करने या निविदाकर्ता का कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि एवं बैंक गारण्टी की राशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण को होगा।
30. निविदा के साथ एनेक्सचर ए,बी,सी,डी,ई, स्वयं को हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करें।
31. सफ़्टाई होने वाले मशीन विद् मैन की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है।

32. निविदादाता जीएसटी अधिनियम 2017 के अधीन पंजीकृत सेवा एजेंसी होनी चाहिए जिसके प्रमाण स्वरूप जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करनी होगी।
33. कार्यादेश से 3 दिवस की अवधि में आदेशानुसार कार्य स्थल पर मशीन विद् मैन की आपूर्ति करनी होगी।
34. फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल जीएसटी राशि को अलग दर्शाया जाकर बिल प्रस्तुत करना होगा संबंधित विभाग में जीएसटी राशि जमा कराने का दायित्व आपूर्तिकर्ता का होगा।
35. भुगतान बिलों से नियमानुसार आयकर की कटौतियां की जावगी।
36. अन्य समस्त शर्तें वित्त विभाग एवं राज्य सरकार के उपायन अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 और सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में उल्लेखित क्रय नियम एवं समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अधीन होगी।

मैंने / हमने उपरोक्तानुसार वर्णित शर्त संख्या 1 से 36 तक को भली भांति पढ़ लिया है एवं समझ लिया है। हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पूर्ण पालना करने के लिए सहमत है। सहमति स्वरूप निविदा की सामान्य शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरे/हमारे द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

दिनांक:

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

Gannar


वित्तीय निविदा
कम्प्यूटर विथ मशीन सप्लाय हेतु दरों का प्रपत्र

क. सं.	सामान का विवरण	नग	स्पेसिफिकेशन (विवरण)	दर प्रति	कुल राशि (संख्या x दर प्रति ईकाई)	जी. एस. टी	कुल योग
1	कम्प्यूटर, प्रिन्टर, यू.पी.एस.	10	computer - Intel Core i3 / Equivalent AMD based computer or higherspeed, RAM 2/4 GB or higher, Hard disk 250 GB or more, 15" Monitor/TFT or bigger, 10/100/1000 mbps LAN Card, CD/DVD Writer Standard Keyboard, Optical Mouse, standard Serial, parallel & USB ports Windows 7 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS Office. Responsibility of software license will be borne by the contractor. Printer – Black and white laser printer with speed 15 ppm or more. For specific needs, Dot matrix/Inkjet printer may be taken in lieu of laser printer. UPS – Online/Offline UPS for above Computer and printer with 30 minutes battery backup.				
	योग						

1. मशीन विद् मैन की मात्रा आवश्यकतानुसार घटायी/बढ़ायी जा सकती है।
2. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने के दिनांक से 3 दिवस की अवधि के भीतर प्रत्येक ब्लॉक (गोविन्दगढ़, दूढ़, फागी, बस्सी, चाकसू, कोटपूतली, पावटा, शाहपुरा, विराटनगर, जमवारामगढ़) पर मशीन विद् मैन की व्यवस्था करनी होगी।
3. उपर उद्धृत की गयी दरें 28.02.2019 तक के लिये विधिमान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।

दिनांक:

हस्ताक्षर निविदादाता

G. Arun 

घोषणा पत्र


मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि हमने निविदा शर्तों के विरुद्ध कोई शर्त नहीं लगाई है यदि कहीं अंकित कर दी गई है तो निविदा स्वतः अस्वीकार मानी जायेगी।

यह है कि जी.एस.टी. 2017 में पंजीकृत है जिसका पंजीयन संख्या दिनांक..... है। यदि यह घोषणा गलत पाई जावे तो विभाग अन्य कार्यवाही के अलावा धरोहर राशि जब्त कर सकेगा। और यदि निविदा स्वीकृत कर ली गई तो उसे निरस्त कर प्रतिभूति/जमानत राशी (सिक्यूरिटी) जब्त कर लेगा।

दिनांक:-

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम एवं पता



G. Annand 

करार पत्र

यह करार पत्र आज दिनांक माह.....सन्.....को एक पक्ष के(जिसे इसमें आगे अनुमोदित निविदा कर्ता कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहां संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों एवं प्रशासकों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) तथा राजस्थान राज्य सरकार (जिसे इसमें आगे सरकार कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहां संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) द्वितीय पक्ष के बीच सम्पन्न किया गया।

1. चूंकि निविदाकर्ता राजस्थान राज्य के उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण के अधीन 10 ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाले मशीन विद् मैन का कार्य कराने की शर्तों में दिये गये तरीके से तथा कार्यदेश संख्या दिनांक में दी गई दरो पर प्रदाय करने के लिए सरकार से सहमत हो गया है।

2. एवं चूंकि सेवा प्रदाय कर्ता ने रुपये की राशि निम्न प्रकार से जमा करायी है:-

(1.) नकद/बैंक ड्राफ्ट/चालान संख्या/बैंकर्स चैक/रसीद संख्यादिनांक.....

द्वारा

(2.) विभागीय प्राधिकारियों के पास विधिवत रेहन रखकर डाकघर बचत बैंक पासबुक के रूप में,

(3.) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों/डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स/किसान विकास पत्रों या किन्ही अन्य स्क्रिप्ट/इन्सट्रुमेंट्स के रूप में, यदि इन्हे सम्बन्धित नियमों के अधीन (प्रमाण पत्र उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार किये जाएंगे) उक्त करार के निष्पादन के लिए प्रतिभूती के रूप में गिरवी रखा जा सकता है।

3. अतः अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है।

(1) कार्यदेश सं. दिनांक..... दी गई दरो पर के मार्फत सरकार द्वारा किये जाने वाले भुगतान के प्रतिफल में सेवा प्रदायकर्ता.....में तथा निविदा एवं संविदा की शर्तों में दिये गये तरीके से उक्त मशीन विद् मैन सप्लाई करेगा।

(2) निविदा सूचना संख्या दिनांक से संलग्न खुली निविदा हेतु निविदा एवं कार्य करने की शर्तों को तथा इस करार पत्र से जुड़ी शर्तों को इस करार पत्र के भाग के रूप में लिया हुआ समझा जाएगा तथा ये इस करार पत्र को निष्पादित करने वाले पक्षकारों के लिए मान्य होगी।

(3) सेवा प्रदायकर्ता कार्यदेश सं. दिनांक..... में उल्लेखित अवधि/तिथि तक निर्धारित मात्रा में मशीन विद् मैन निर्धारित स्थल पर प्रदाय करेगा।

4. करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार पत्र के निवार्चन या व्याख्या से सम्बन्धित सभी प्रश्न सरकार (उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण) द्वारा विनिश्चित किये जाएंगे तथा सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

इसकी साक्षी मे इसमे पक्षकारों ने आज दिनांक माह..... सन..... को अपने हस्ताक्षर किये।

हस्ताक्षर

द्वितीय पक्ष

उपनिदेशक

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जयपुर ग्रामीण

साक्षी सं. 1

साक्षी सं. 2

साक्षी सं. 1

साक्षी सं. 2

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

- a. have controlling partners/ shareholders in common; or
- b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Decl

Annex A

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to
..... in response to their Notice Inviting Bids No.
Dated:, I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public
Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition.



Gadmaur Or

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is _____

The designation and address of the Second Appellate Authority is _____

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality

(5) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal


(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

He may also order for inspection of documents and relevant records or

Ganesh 

FORM No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement
Act, 2012

Appeal No of

Before the (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against
and name and designation of the officer / authority
who passed the order (enclose copy), or a
statement of a decision, action or omission of
the Procuring Entity in contravention to the provisions
of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented
by a representative, the name and postal address
of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

..... (Supported by an
affidavit)

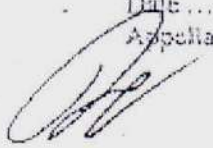
7.

Prayer:

Place

Date

Appellant's Signature


G. Anand

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.



If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.


(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.


Annexure 

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted


Gannant Or

Annexure E

Clause 1: Fair Wage Clause

- (a) The Contractor shall pay not less than fair wages/minimum wages to labours engaged on the work as revised from time to time by the Government, but the Government shall be liable to pay any thing extra for it except as stipulated in price escalation clause (clause 10) of the agreement.

Explanation: "Fair Wage" means minimum wages for time or piece work, fixed revised by the State Government under the Minimum Wages Act, 1948.

The Contractor shall, notwithstanding the provision of any contract to the contrary, cause to be paid fair wages to labourers indirectly engaged on the work, including any labour engaged by his sub-contractors in connection with the said work as if the labourers have been immediately or directly employed by him.

- (b) In respect of all labourers, immediately or directly employed on the work, for the purpose of the Contractor's part of this agreement, the Contractor shall comply with or cause to be complied with the Public Works Department Contractor's Labour Regulations made, or that may be made by the Government, from time to time, in regard to payment of wages, wages period, deductions from wages, recovery of wages not paid, and unauthorised deduction of maintenance of wages register, wage card, publication of scale of wages and other terms of employment, inspection and submission of periodical returns and other matters of a similar nature.

- (c) The Engineer-in-charge shall have the right to deduct from the money due to the Contractor any sum required or estimated to be required for making good the loss suffered by a worker or workers, by reasons of non-fulfilment of the conditions of the contract, for the benefit of a worker or workers, non-payment of wages or of deductions made there from, which are justified by the terms of the contract, or as a result of non-observance of the aforesaid regulations.

- (d) Vis-à-Vis the Municipal Corporation Jaipur, the Contractor shall be primarily liable for payments to be made and for the observance of the regulations aforesaid, without prejudice to his right to claim indemnity from his subcontractors.

- (e) The regulations, aforesaid, shall be deemed to be part of this contract and any breach thereof shall be breach of the contract.

Clause 2: Contractor to engage technical staff

The Contractor shall engage the technical staff, as follows, on the contract works:-
For works costing Rs. 100 lac and above- One Graduate Engineer.

For works costing between Rs. 50 lac to Rs. 100 lac- One qualified diploma holder having experience of not less than 3 years.

For works costing between Rs. 15 lac and Rs. 50 lac- One qualified diploma holder.

The technical staff should be available at site, whenever required by Engineer-in-charge to take

Clause 3:
The Contractor shall comply with the provisions of the Apprenticeship Act, 1961, and the Rules and Orders issued, there under, from time to time. If he fails to do so, his failure will be a breach of contract. The Contractor shall also be liable for any pecuniary liability arising on account of violation by him of the provisions of the said Act.

Clause 4: Safety Code
The Contractor shall follow the safety code of electricity Strictly.

Clause 5: Relatives barred from tendering
The Contractor shall not be permitted to tender for works in Circle, in which his near relative posted as Divisional Accountant or as an officer in any capacity between the grades of Superintending Engineer and Assistant Engineer (both inclusive). He shall also intimate the name of persons, who are working with him in any capacity, or are subsequently employed by him and who are near relatives to any gazetted officer in the Organization/Department. Any breach of this condition by the Contractor would render him liable to be removed from the approved list of contractors of the Department. If such facts are noticed (a) before sanction of tender, his offer shall be declared invalid and earnest money shall be forfeited, (b) after sanction of the tender then the tendering authority may at his discretion forfeit his earnest money, performance guarantee, security deposit and enlistment deposit and the work/remaining work may allot to any registered contractor on the same rates as per rules.

Note: By the term 'near relative' is meant wife, husband, parents and grand-parents, children and grand children, brothers and sisters, uncles and cousins and their corresponding in-laws.

Clause 6: Retired Gazetted Officers barred for 2 years
No Engineer of Gazetted rank or other Gazetted Officer, employed in Engineering or Administrative duties in an Engineering Department of the Government of Rajasthan, is allowed to work as a Contractor for a period of 2 years of his retirement from Government service without the previous permission of Government of Rajasthan. The contract is liable to be cancelled, if either the Contractor or any of his employees is found, at any time, to be such a person, who had not obtained the permission of Government, as aforesaid, before, submission of the tender or engagement in the Contractor's service, as the case may be.

Clause 7: Quality Control
Municipal Corporation Jaipur shall have right to exercise proper Quality Control measures. The Contractor shall provide all assistance to conduct such tests and shall bear the cost of all tests,

(whether full constructed or not) and all materials.

temporary buildings and other things connected therewith, shall be at the risk of the contractor the work has been delivered to the Engineer-in-charge, and a certificate from him, to the obtained.

Clause 9: Death of Contractor

Without prejudice to any of the rights or remedies under the contract, if the Contractor dies the heirs of the Contractor or the Chief Engineer or duly authorised Engineer shall have the option of terminating the contract without any compensation.

Clause 10 : Force Majeure

Neither party shall be liable to each other, for any loss or damage, occasioned by or arising from acts of God such as-unprecedented floods, volcanic eruptions, earthquake or other invasion of nature and other acts.

Clause 11: General Discrepancies and errors:

In case of percentage rate tenders, if there is any typographical or clerical error in the rates shown in the department in the "G" Schedule, the rates as given in the basic Schedule of Rates of the Department for the area shall be taken as correct.

Clause 12 : Post payment Audit & Technical Examination:

The Government shall have right to provide a system of per-check of Contractor's bill by a special Organization, and payment by an Engineer or an Accounts Officer/ Sr. Accounts Officer/ Chief Accounts Officer/ Financial Advisor, as the Government may in its absolute discretion prescribe. Any over-payments/ excess payment detected, as a result of such per-check post-check Contractor's bill, can be recovered from the contractor's bills in the manner, herein before provided and the Contractor will refund such over/ excess payments.

Clause 13 : Check Measurements:

The department reserves to itself, the right to prescribe a scale of check measurement of work in general, or specific scale for specific works or by other special orders (about which the decision of the department shall be final) Checking of measurement by superior officer shall supersede measurements by the subordinate officer and the former will become the basis of the payment. Any over/excess payment detected, as a result of such check measurement or otherwise at any stage up to the date of completion and the defect removal period specified else-where in this contract, shall be recoverable from the Contractor, as any other dues payable to the Government.

Clause 14: Check Measurements-

The Contractor in course of the work should understand that all materials e.g. stone, bricks, steel and other materials obtainable in the work by dismantling etc. will be considered as the property of Government and will be disposed off to the best advantage on the Government. As per direction of the Engineer-in-Charge.

Clause 15: Recovery from Contractors:

Whenever any claim against the Contractor for the payment of a sum of money arises out of or under the contract, the Department shall be entitled to recover such sum by appropriation in part or whole of the Performance Guarantee and / or Security Deposit. Security Deposit at the time of enlistment of the Contractor. In the event of the security being insufficient, or if no security has been furnished thereafter, may become due to the Contractor, under this or any other contract with the Government of Rajasthan. Should this sum be not sufficient to cover the full amount recoverable the Contractor shall pay to the Department on demand the balance remaining dues.

The department shall, further, have the right to affect such recoveries under Public Debt Recovery Act.

Clause 16: Jurisdiction of Court:

In the event of any dispute arising between the parties hereto, in respect of any of the matters comprised in this agreement, the same shall be settled by a competent court having jurisdiction at the place, where agreement is executed and by no other court, after completion of proceedings under Clause 23 of this contract.



For Approval Advertising



G. N. V. 12